23.03.2018

पांचवा भारतीय मक्का शिखर सम्मेलन 2018

श्री राधा मोहन सिंह, माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री, कृषि, एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उदघाटन भाषण

मैं इस फसल पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं और भारत के मक्का शिखर सम्मेलन के पांचवें संस्करण का आयोजन करने के लिए फिक्की को बधाई देता हूं। वैश्विक आधार पर मक्का की खेती लगभग 160 देशों के तकरीबन 150 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती है। इन देशों में बड़े पैमाने पर मृदा, जलवायु में विविधता पाए जाने के साथ जैव विविधता और प्रबंधन अभ्यासों पर भी अलग-अलग तरीके से अमल किया जाता है। इन देशों के द्वारा विश्व का 36 प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन (782 मीट्रिक टन) प्राप्त होता है। अमेरिका विश्व में मक्का उत्पन्न करने वाला सबसे बड़ा देश है। यह देश विश्व के कुल मक्का उत्पादन का 35 प्रतिशत भाग पैदा करता है। उल्लेखनीय है कि भारत में मक्का की औसत उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 2.43 टन है।

खाद्यान्न संबंधी मांगों और उपभोक्ताओं की पसंद को वैश्विक परिदृश्य पर देखने के बाद पता चल रहा है कि मक्का अनेकों देशों विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है। मक्का भारतीय लोगों के बीच गेहूं और चावल के बाद तीसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत में आधे से अधिक मक्का का उत्पादन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान इन चार राज्यों में किया जाता है। इस समय भारत विश्व में मक्का के पांच बड़े निर्यातकों में शामिल है। इस समय खाद्य फसल के रूप में मक्का का उपयोग केवल 25 प्रतिशत लोगों तक ही सिमित है। इस समय संकर जाति की मक्का की खेती का क्षेत्र पर्याप्त रूप से बढ़ रहा है जिसके फलस्वरूप कम कीमत पर लोगों को पोषक आहार प्राप्त हो रहा है इसकी पोषकता को दृष्टिगत रखते हुए इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है।

मक्का विजन 2022 पर एक ज्ञान रिपोर्ट के साथ आने के लिए मैं फिक्की और पीडब्ल्यूसी (प्राईवॉटरहाउस कूपर्स) को बधाई देता हूं। मैं खुश हूं कि फिक्की और पीडब्ल्यूसी (प्राइसवाटरहाउस कूपर्स) 2022 तक दोहरीकरण के किसानों की आय का सरकारी दृष्टिकोण

प्राप्त करने के तरीके पर विचार कर रहे हैं। फिक्की द्वारा एक छत के नीचे पूरे मक्का समूह को लाने के लिए प्रयासों की सराहना योग्य है। इस एक दिवसीय शिखर सम्मेलन में कुक्कुट और स्टार्च उद्योग की उपस्थिति का संकेत है कि देश में मक्का की एक गंभीर मांग है।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि विपणन पर सुधारों को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीन कृषि बाज़ार (जीआरएएम) विकसित करने के लिए विशेष घोषणाओं के साथ 2000 करोड़ रुपये का एक कोष निधि के आवंटन के साथ विशेष घोषणाओं के हैं मुझे सुझाव है कि इस कमरे में मौजूद मक्का कृषि व्यवसायी कंपनियों को कृषि विपणन में विभिन्न अवसरों की खोज के द्वारा मक्का के किसानों के साथ मिलकर बनाने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए।

हमारे देश में मक्का के खेती के क्षेत्र में केवल 15% सिंचाई की जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश की उपलब्धता को प्राप्त करने के लिए अब, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) से जोड़ने का समय है ताकि अश्चित सिंचाई (हर खेत को पानी) के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार हो, पानी की बर्बादी कम करना करने के लिए खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार हो, सटीक-सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियां (अधिक फसल प्रति डंप) जैसे तकनीकें गोद लेने मे वृद्धि हो और जिससे देश में मक्का की फसल की उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार आए

अनुसंधान कार्यक्रम: आईसीएआर-भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (आईआईएआर), लुधियाना को यह कार्य सौंपा गया है कि वह मक्का की फसलों में उत्पादन, उत्पादकता और संधारणीयता को बढ़ाने के लिए आधारभूत, कार्यनीतिक और अनुप्रयोजित अनुसंधान कार्य करें। यह संस्थान मक्का से जुड़ी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) से संबंधित कार्यों का समन्वय करने के साथ-साथ विस्तार और अभिगम्य कार्यक्रमों को भी संचालित करता है।

विकास कार्यक्रम: इसी प्रकार कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के फसल प्रभाग द्वारा संचालित एनएफएसएम कार्यक्रम के तहत प्रदर्शनों, बीज वितरण, बीज उत्पादन, आईएनएम एवं आईपीएम, फलैक्सी हस्तक्षेपों यथा स्थानीय पहलों/मशीनों/जल बचत उपकरणों/प्रशिक्षण कार्यों/पीएमटी/लंबित देयताओं आदि जैसे चयनित हस्तक्षेपों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर 28 राज्यों के 265 जिलों में मक्का की खेती को बढ़ावा

दिया जा रहा है। वर्ष 2015-16 से केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 की भागीदारी पद्धति और केन्द्र सरकार तथा पूर्वोत्तर एवं तीन पर्वतीय राज्य के बीच 90:10 की भागीदारी पद्धति के आधार पर इस मिशन को कार्यान्वित किया जा रहा है।

एनएफएसएम के तहत फसल प्रभाग द्वारा किए गए प्रयासों और देश में मक्का के सतत उत्पादन हेतु अपेक्षित प्रौद्योगिकियों के सृजनार्थ आईसीएआर-आईआईएमआर ने मक्का समुदाय द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के फलस्वरूप देश में हाल ही के वर्षों में मक्का उत्पादन के क्षेत्र में जबरदस्त उपलब्धियां दर्ज हुई है। वर्ष 1950-51 के दौरान भारत में केवल 1.73 मीट्रिक टन मक्का का उत्पादन हुआ था जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 25.89 मीट्रिक टन हो गया है और उम्मीद की जाती है कि यह मात्रा 2017-18 में बढ़कर 27.0 मीट्रिक टन हो जाएगी। ऐसा क्षेत्र और उत्पादकता में वृद्धि होने के कारण संभव हुआ है।

उम्मीद है कि वर्ष 2025 तक भारत को 50 मीट्रिक टन मक्का खाद्यान्नों की जरूरत होगी जिनमें से 32 मीट्रिक टन का इस्तेमाल आहार क्षेत्र, 15 मीट्रिक टन का औद्योगिक क्षेत्र और 2 मीट्रिक टन का आहार क्षेत्र तथा 1 मीट्रिक टन का बीज एवं विविध क्षेत्र में किया जायेगा। आज के एकल क्रास संकर युग में भारत में मक्का की उत्पादकता (प्रति हेक्टेयर 2.56 टन) 5.52 टन प्रति हेक्टेयर की वैश्विक औसत उत्पादकता की तुलना में बहुत कम है। इस कम उत्पादकता का प्रमुख कारण जमीन पर अजैविक दबावों का ज्यादा होना है। ये दबाव इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि 70 प्रतिशत मक्का की खेती वर्षा सिंचित क्षेत्रों में की जाती है।

आगे की कार्यनीति: मक्का की क्षमता का एहसास करने के लिए आगे, "भविष्य में अनाज का फसल" को तकनीकी नवाचारों के आसपास के रणनीतियों और हस्तक्षेपों की एकत्रीकरण, उत्पादक एकत्रीकरण और संबंधों को बढ़ावा देना, आधारभूत संरचना का समर्थन करना, पीपीपी संबंधों को निरस्त करना और कई नीतिगत हस्तक्षेपों को सुगम बनाना है। मक्का आधारित सिलएज बनाने वाली इकाइयों की स्थापना के लिए पीपीपी अवसरों को स्थापित करना, मक्का आधारित कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) और मक्का आधारित फार्म मशीनरी बैंकों के निवेश के लिए संभव अवसर के रूप में आते हैं।

मकई में उपलब्ध श्रम का उपयोग कम करने और मैकेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए इन मार्गों को टैप करना और बढ़ाया जाना चाहिए। अब से लेकर 2050 के बीच विकासशील

देशों में मक्का की मांग दुगुनी हो जाएगी। वर्ष 2025 तक विकासशील देशों में वैश्विक आधार पर मक्का का उत्पादन सबसे अधिक किया जायेगा। भारत में उत्पादित मक्का का अधिकांश भाग पशुओं के आहार के रूप में उपयोग में लाया जाता है और इसका बहुत कम भाग इंसानों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए विचारणीय बात यह है कि इससे प्राप्त होने वाले लाभों को अभी समझा नहीं गया है।

स्वास्थ्य और पोषाहारीय अनुसंधान कार्यों, विपणन माध्यमों के जरिए, उत्पाद संवितरण कार्यों, उपयोगकर्ताओं के और उपभोक्ताओं के ईष्टतम लाभों के साथ मक्का उत्पाद विकास से जुड़े संगठनों को सुदृढ़ करने संबंधी संधारणीय कार्यनीतियां आज के विश्व की जरूरत है। पोषाहारीय तत्वों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने और जैव समर्थित मक्का के प्रभाव को समझाने से पोषाहारीय सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। मक्का के जरिए आंतरिक खपत के साथ निर्यात की भी जबरदस्त संभावनाएं मौजूद है। हमें इस संबंध में वैश्विक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए इन अवसरों से लाभांवित होने का प्रयास करना है।

मैं कार्यक्रम की एक महान सफलता की कामना करता हूं।